Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2017: 5.068, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, AUG-SEPT 2018, VOL- 6/29

शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन में 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' की भूमिका का मूल्याँकन (उ0प्र0 के अलीगढ़ मण्डल के कासगंज जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

मनोज कुमार

(शोध–छात्र) समाजशास्त्र, के0ए0 (पी0जी0) कॉलेज, कासगंज (उ0प्र0), (सम्बद्ध : डॉ0 भीमराव अम्बेडकर वि0वि0, आगरा)

Abstract

युवा ऊर्जा किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने वाली ताकत के रूप में उभरती है बशर्ते उसे प्रभावी रूप से दिशा दी जाये। युवा जनसंख्या के मामले में भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा भण्डार है फिर भी भारतीय नियोक्ता कुशल मानव बल की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहे हैं। जिसका मुख्य कारण रोजगार के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की कमी का होना है। 'श्रम ब्यूरो की 2014 की रिपोर्ट' के अनुसार भारत में औपचारिक रूप से कुशल कार्य बल का वर्तमान आकार केवल 2 प्रतिशत है। इसके अलावा पारम्परिक शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के बड़े वर्ग की रोजगार सम्बन्धी योग्यता की चुनौती भी है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था शानदार मस्तिष्कों को जन्म दे रही है लेकिन रोजगार विशेष के लिए जरूरी कौशल की उसमें कमी है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से निकल रही प्रतिभा और रोजगार योग्य कौशल की सम्भावना एवं मानक के मामले में उसकी अनुकूलता के बीच बड़ा अन्तर है। इस वर्ग की जनसंख्या में राष्ट्र तथा पूरी दुनिया की कौशल सम्बन्धी जरूरत पूरी करने की क्षमता है। जरूरत है तो बस सटीक एवं पर्याप्त कौशल विकास तथा प्रशिक्षण की, जो इस ताकत को तकनीकी रूप से कुशल मानव बल के सबसे बड़े श्रोत में बदल सकते हैं। भारत जिस जनसांख्यिकीय लाभांश के भरोसे बैठा है उसका लाभ मिलने का सबसे उपर्युक्त समय यही है। सितम्बर 2013 में जारी जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक युवा 15 से 24 आयु वर्ग में हैं। किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान; दो प्रेरक शक्तियाँ हैं। वर्तमान वैश्विक माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की चुनौती से निपटने तथा युवा सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मेक इन इण्डिया' सोच के साथ 16 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय स्तर पर 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' (PMKVY) को लाँच किया। योजना का मौलिक उद्देश्य युवाओं के लिए कौशल विकास को एक सार्थक; उद्योग सम्बन्धी कौशल आधारित पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है जिसका 12000 रू0 प्रति लाभार्थी खर्च भी शासन वहन करता है जिसके लिए उम्मीदवार को अपनी रूचि का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रशिक्षणार्थी को अपने क्षेत्र के चयनित प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण तथा मूल्याँकन शुल्क का भुगतान करना होता है, और नामाँकन हेतु आवेदन करते समय उम्मीदवार को अपना 'आधार कार्ड' तथा 'बैंक खाता' जमा करना होता है। कौशल प्रशिक्षण (जिसकी अवधि 3 माह से 1 वर्ष अधिकतम होती है) पूरा होने पर युवा प्रशिक्षणार्थी को ''नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉरपोरेशन'' (NSDC) जो एक गैर लाभ कम्पनी है, द्वारा नियुक्त ''मूल्याँकन एजेन्सी ''सेक्टर स्किल काउन्सिल'' (SSC) की जाँच–प्रक्रिया द्वारा सफल मूल्याँकित किए जाने पर शासन की ओर से एक 'प्रमाण–पत्र' दिया जाता है जो उन्हें रोजगार पाने और अपना भविष्य उज्जवल बनाने में सहायक होता है। कौशल प्रशिक्षण के प्रति उम्मीदवार को शासन द्वारा औसतन 8000 रू0 'मौद्रिक पुरस्कार' प्रोत्साहन बतौर भी प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय शर्त यह है कि योजनान्तर्गत विशेषकर ऐसे युवाओं, जो कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ दिया हो; ऐसे छात्रों पर ध्यान केन्द्रित कर वरीयताएं देनी होंगी। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ 'व्यवहार कुशलता' तथा 'व्यवहार में रचनात्मक परिवर्तन' भी शामिल हैं। 'कौशल व उद्यम विकास' वर्तमान सरकार की उद्यम विकास मंत्रालय की 'मेक इन इण्डिया' अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे एक मिशन के तौर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना की वेबसाइट (www.pmkvy official.org) है जिस पर योजना की सम्पूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हैं।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

'साहित्य का पुनरावलोकन' (Review of Literature) :

आज शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के बीच बेमेल बहुत अधिक हैं। 'मैकेन्जी की रिपोर्ट 2017', के अनुसार केवल 54 प्रतिशत युवा मानते हैं कि माध्यमिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने से उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। 10वीं कक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच 56 प्रतिशत छात्र पढ़ना छोड़ देते हैं। इन सभी तथ्यों और धारणाओं के बीच कुछ ही युवाओं को रोजगार तथा प्रशिक्षण मिलता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 53 प्रतिशत भारतीय नियोक्ताओं को लगता है कि आरम्भिक स्तर के पदों पर रोजगार विरत व्यक्तियों का प्रमुख कारण कौशल में कमी है। इस प्रकार रोजगार एवं रोजगार की योग्यता के बीच बड़ी खाई है। साम्प्रत देश के सामने मुख्य चुनौती है कि 25 वर्ष से कम उम्र वाले उन लाखों युवाओं के लिए रोजगार ढूंढ़ना जो वर्तमान में भारत की जनसंख्या के लगभग 50 प्रतिशत हैं एक चुनौती है।[1]

इन्द्रभूषण महापात्र[2] (राष्ट्रीय सहाराः भारत के शिक्षित युवा चौराहे परः 30 जुलाई 1989:13) ने अपने आनुभविक अध्ययन में पाया है कि शिक्षित युवाओं में से हर दूसरा युवा बेरोजगार है, जिसे योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारी शिक्षा के उदारीकरण से रोजगार कभी सुलभ नहीं होंगे। इसलिए हमें कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए ताकि रोजगार के लिए निरर्थक भटकना न पड़े।

प्रख्यात समाज वैज्ञानिक **रूद्दत हुसैन**[3] (नौकरी नहीं; काम ढूँढना होगा, **हस्तक्षेप डेस्क**, जे0एन0यू0 दिल्ली, 30 सितम्बर 2000, पृश्ठ 6) का मानना है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी अब इस कदर बढ़ चुकी है कि शिक्षित युवाओं को अब नौकरी नहीं; कौशल के अनुरूप काम ढूँढने होंगे। अगले दशक में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के निजीकरण की वजह से केवल शिक्षित बेरोजगार ही बेरोजगार नजर आवेंगे या फिर उन्हें अपनी रूचि के प्रशिक्षण लेकर अपने निजी उद्यम स्थापित करने होंगे।

(कु0) सरेखा[4] (शिक्षित बेरोजगारी के कारणः 1992, प्रकाशित शोध पत्र, 'योजना' पत्रिका) के अनुसार शिक्षितों की बेरोजगारी के मूल कारण वही हैं जो देश में सामान्य बेरोजगारी के मूल कारण हैं। इसके उन्मूलन के लिए भासन को स्वरोजगारों के विभिन्न संसाधन सृजित करन के लिए 'रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम' चलाने होंगे एवं व्यावसायिक तथा रोजगारपरक शिक्षा पर बल देना होगा।

प्रो0 सक्सैना राज कुमार[5] (शिक्षितों की बेरोजगारी– समस्या एवं समाधान, विवेक प्रकाशन, दिल्लीः 1996;82) के शब्दों में शिक्षित बेरोजगारी का मूल कारण यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक नौकरी के लिए पढ़ रहा है; न कि शिक्षा पाकर अपना निजी उद्यम स्थापित करने के लिए। वह एनकेन प्रकारेण नौकरी पाना चाहता है, इससे सफेदपोश अपराध बढ़ रहे हैं।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

लवानिया एम0एम0[6] (1997) के अनुसार 'शिक्षित बेरोजगारी' एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति के पास कोई नौकरी या काम धन्धा नहीं होता है परन्तु वह कोई ऐसी नौकरी या काम धन्धा तलाश रहा है, या रोजगार पाने की इच्छा रखता है, जिस में उसकी योग्यता के अनुसार वेतन मिल रहा हो।

''हस्तक्षेप डैस्क''[6] (30 सितम्बर 2000, पष्ठ 6) के अनुसार भारत में शिक्षित बेरोजगारी अब इस तरह बढ़ गयी है कि शिक्षित युवाओं को नौकरी नहीं; काम ढूँढ़ने होंगे। अगले द ाक में उच्च शिक्षा के निजीकरण से शिक्षित बेरोजगार ही बेरोजगार नजर आयेंगे; या फिर निजी उद्यम स्थापित कर रोजगार पाने होंगे।

त्रिपाठी ए0के0[8] (2003:132) के अनुसार ''हमारे देश के योजनाकारों ने एक हिसाब ईमानदारी से नहीं लगाया कि आबादी कितनी तथा किस दर से बढ़ रही है, और रोजगारों के कितने अवसर पैदा हो रहे हैं, प्रतिवर्ष कितने ग्रेजुएट निकल रहे हैं, और उनके योग्य रोजगार हर साल कितने सुलभ हो रह हैं। परिणामतः 'शिक्षित युवा बेरोजगारों' की एक बड़ी फौज निरन्तर खड़ी हो रही है।''

बाबा जी0डी0 (2005)[9] ने अपनी पुस्तक **'ऐम्प्लाइमेण्ट, अन–ऐम्प्लाइमेण्ट एण्ड फुल–ऐम्प्लाइमेण्ट'** में लिखा है कि परम्परागत ि ाक्षा; बेरोजगारी दर में वृद्धि करती है अतः इसके स्थान पर तकनीकी/रोजगारपरक शिक्षाओं को प्रोत्साहित करने की दि ाा में सतत् प्रयासों की वि ोश आव यकता है। अन्यथा की स्थिति में 'बेकारी' तथा 'बेकारों की संख्या' में वृद्धि होगी ही। 'फुल–ऐम्प्लाइमेण्ट' के लिए भारत में उचित तकनीकी प्रशिक्षण शिक्षण संस्थानों एवं ऐस ही रोजगार प्रदान करने वाले संसाधनों का नितान्त अभाव है। शोधार्थी का मानना है कि 'शिक्षा' जापान की तरह नौकरी के लिए नहीं; अपितु 'योग्यता' के लिए प्रदान की जानी चाहिए जबकि भारत में प्रत्येक व्यक्ति नौकरी के लिए शिक्षा ग्रहण करता है; न कि उद्यम (रोजगार) स्थापित करने के लिए। अस्तु विद्यार्थियों तथा जन मानस में मानसिक एवं दृष्टिकोण बदलाव की जरूरत है।

अध्ययन के उद्देश्य :

(1) निदर्शितों की वैयक्तिक तथा सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी करना।

(2) 'प्रधान मंत्री कौशल विकास' योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं द्वारा अर्जित नौकरियों तथा उद्यमों/रोजगारों की प्राप्ति का अध्ययन करना।

(3) शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन में 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' की भूमिका का विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में मूल्याँकन कर; सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध–परिकल्पना (Research Hypothesis) :

शोध–समस्या के सन्दर्भ में परिकल्पना रही है कि, ''शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन में 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' एक महत्वाकाँक्षी योजना तथा परिणाम आधारित सार्थक पहल है, ''जिसने युवा वर्ग की सोच में बदलाव लाया है।''

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पद्धतिशास्त्र / शोध–प्राविधि (Research Methodology) :

प्रस्तुत शोध–प्रपत्र उ0प्र0 के अलीगढ़ मण्डल के जिला कासगंज में क्रियान्वित 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' (PMKVY) के अन्तर्गत (1 जुलाई 2017 से अद्यतन) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय पॉलीटैक्निक तथा अन्य 3 Partner Training Centres प्राइवेट कौशल प्रशिक्षण संस्थानों से अपनी रूचियों के विभिन्न तकनीकी ट्रेड्स में लाभान्वित हुए कुल 503 कौशल प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं में से ''संयोग न्यादर्श विधि की लॉटरी पद्धति'' (Lottery Technique of Random Sampling Method) द्वारा चयनित कुल 200 न्यादर्शितों से ''साक्षात्कार–अनुसची'' के माध्यम से प्रत्यक्ष साक्षात्कारों द्वारा संकलित प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। 'तथ्य–संकलन' में 'क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि' अपनायी गयी है। द्वितीयक तथ्यों का संकलन–कार्य : National Skill Development Agency (NSDA), Sector Skill Council (SSC), Pradhan Mantri Kaushal Centre (PMKC) 'जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध निदेशक; राज्य रोजगार सृजन अभिकरण की नियोक्ता संस्था 'नीफा' से है'; से किया गया है। ताकि अध्ययन तथ्यपरक व मौलिक रूप में सम्पादित किया जा सके। तथ्यों के विश्लेषण तथा निर्वचन में 'साँख्यकीय विश्लेषण विधि' अपनायी गयी है। तत्सम्बन्धित प्राप्त विवरण अग्रॉकित हैं :

तथ्य–संकलन, विश्लेषण तथा निर्वचन / सामान्यीकरण :

तालिका नं0 (1) : न्यादर्शों की वैयक्तिक तथा समाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

क्र0	परिवर्त्य (Variables)	सूचनादाताओं की आवृत्तियाँ / प्रतिशत				समस्त
1	धर्मवृत्तिका	हिन्दू 154(77.00)	इस्लाम 36(18.00)	अन्य 10(05.00)	––	समस्त 200(100.00)
2	पृष्ठभूमि / परिवेश	ग्रामीण 58(29.00)	नगरीय 86(43.00)	ग्रामीण–नगरीय 56(28.00)	––	समस्त 200(100.00)
3	लिंग–भेद	बालक 106(53.00)	बालिकाएं 94(47.00)	––	––	समस्त 200(100.00)
4	जाति / वर्ग	सामान्य 70(35.00)	पिछड़ी 94(47.00)	अनुसूचित 32(16.00)	अनु0ज0जा0 4(02.00)	समस्त 200(100.00)
5	शिक्षा–स्तर	10^{th} फेल 54(27.00)	10^{th} पास 88(44.00)	12^{th} पास 36(18.00)	12^{th} से ऊपर 22(11.00)	समस्त 200(100.00)
6	कौशल प्रशिक्षण सन्दर्भ	* 54(27.00)	कम्प्यूटर 82(41.00)	प्लम्बिंग 20(10.00)	अन्य (**) 44(22.00)	समस्त 200(100.00)
7	सामाजिक–आर्थिक स्तर	निम्न 40(20.00)	निम्न–मध्यम 70(35.00)	मध्यम 56(28.00)	उच्च 34(17.00)	समस्त 200(100.00)

*संकेतः *सिलाई, कढ़ाई बुनाई, ब्यूटीशियन, पेण्टिंग, फ्रूट प्रिजर्वेशन*

***बिजली फिटिंग, मोटर बाइण्डिंग, टर्निंग, खाद्य–प्रसंस्करण, फार्मिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक, हस्तशिल्प कार्य*

प्रसंगाधीन तालिका नं0 (1) के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण के आलोक में स्पष्ट है कि अध्ययनार्थ चयनित स्किल कार्ड प्राप्त कुल 200 न्यादर्शितों में सभी धर्मों, जाति वर्ग, ग्रामीण और नगरीय पृष्ठभूमि तथा सामाजिक–आर्थिक स्तरों के बेरोजगार बालक–बालिकाओं जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

मध्य है, का प्रतिनिधित्व है जिन्होंने केन्द्र सरकार की महत्वाकाँक्षी व्यवसायपरक/रोजगार सृजक 'कौशल विकास योजनान्तर्गत' विभिन्न प्रकार के (अपनी रूचि के) तकनीकी प्रशिक्षण निःशुल्क प्राप्त कर 'स्किल प्रमाण–पत्र' प्राप्त किए हैं ताकि वे सरकारी/निजी क्षेत्रान्तर्गत नौकरी पा सकें या फिर 'स्वरोजगार' स्थापित कर सकें। इसी कड़ी में प्रस्तुत शोध–पत्र द्वारा 'PMKVY' का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मूल्याँकन एक लघु प्रयास है।

सर्व प्रथम ''स्किल कार्ड प्राप्त'' सभी 200 न्यादर्शितों से व्यक्तिगत साक्षात्कारों के समय पृथक–पृथक प्रश्न पूछा गया कि ''प्रधान मंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत स्किल कार्ड (उद्यमिता प्रमाण–पत्र) मिल जाने के पश्चात् आपको कोई लाभ हुआ है?'' सूचनादाताओं से प्राप्त प्रत्युत्तरों पर निम्न तालिका नं0 (2) संक्षिप्त प्रकाश डालती है :

तालिका नं0 (2) : 'उद्यमिता प्रमाण–पत्र' (Skill Certificate) प्राप्त कर लेने के पश्चात् अर्जित लाभ

क्र0	उद्यमिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् लाभ		आवृत्तियाँ		प्रतिशत	
1	नौकरी मिल गयी है :	निजी क्षेत्र में	25	33.00	12.50	16.50
		सरकारी क्षेत्र में	8		04.00	
2	स्व–व्यवसाय (रोजगार) स्थापित कर लिए हैं		110		55.00	
3	स्व–रोजगारों की स्थापना हेतु प्रयासरत हैं		57		28.50	
समस्त			200		100.00	

प्रस्तुत प्रसंगाधीन तालिका नं0 (2) के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण के आलोक में स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत उद्यमिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेने वाले 200 न्यादर्शों में से 33(16.50%) न्यादर्शों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें नौकरी मिल गयी है (मात्र 4% को सरकारी तथा 12.50% को निजी क्षेत्रान्तर्गत); जबकि 110(55%) न्यादर्शों ने स्व–व्यवसाय/रोजगारों के संसाधन सृजित कर लिए हैं अर्थात् 71.50% न्यादर्शों द्वारा नौकरी पा लेना व स्व–रोजगार स्थापित कर लिए हैं जो यह स्पष्ट करता है कि प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, शिक्षित बरोजगारी उन्मूलन में सहायक है। परन्तु 57(28.50%) न्यादर्श अभी भी स्व–रोजगार स्थापित करने हेतु अद्यतन प्रयासरत हैं, जो अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थापित 'राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों' से अनुदानित ऋण स्वीकृत करा रहे हैं। निम्न तालिका नं0 (3) स्व–व्यवसायरत (रोजगाररत) कुल 110 तथा प्रयासरतों कुल 57 द्वारा कौशल प्रशिक्षणोपरान्त उद्यम स्थापनाओं हेतु प्रदत्त वरीयताएं दर्शाती है :

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं0 (3) : स्व–रोजगाररत तथा प्रयासरतों द्वारा वरीयताएं

क्र0	कौशल प्रशिक्षण एवं स्किल सर्टीफिकेट विवरण	स्व–रोजगाररत न्यादर्श रोजगार हेतु प्रदत्त वरीयता				समस्त (%)	कोटि क्रम	प्रयासरत न्यादर्श रोजगार हेतु प्रदत्त वरीयता				समस्त (%)	कोटि क्रम
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ			प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ		
1	सिलाई, कढ़ाई, बुनाई/टेलरिंग	5	2	–	1	8(07.27)	7	6	4	–	–	10(17.54)	2
2		3	1	2	–	6(05.45)	8	7	2	–	–	9(15.79)	3.5
3	ब्यूटीशियन/पार्लर	1	1	1	1	4(03.64)	9.5	–	2	–	1	3(02.74)	7
4	पेण्टिंग	1	–	–	–	1(00.91)	12	–	–	–	–	–(00.00)	–
5	फ्रूट प्रिजर्वेशन	20	3	4	2	29(26.36)	1	6	3	1	1	11(19.29)	1
6	कम्प्यूटर	8	2	–	5	15(13.64)	2	4	3	–	–	7(12.28)	5
7	बिजली मिस्त्री	7	–	3	1	11(10.00)	3	1	1	–	–	2(03.52)	8.5
8	मोटर बाइंडिंग	5	–	3	2	10(09.09)	4.5	2	–	–	–	2(03.52)	8.5
9	प्लम्बिंग	2	4	2	2	10(09.09)	4.5	–	–	–	–	–(00.00)	–
10	टर्निंग	3	–	–	–	3(02.73)	11	–	–	–	–	–(00.00)	–
11	खाद्य–प्रसंस्करण	7	1	1	–	9(08.18)	6	5	3	–	1	9(17.79)	3.5
12	फार्मिंग/ट्रैक्टर मैकेनिक हस्तशिल्प कार्य	3	–	1	–	4(03.64)	9.5	2	1	1	–	4(07.03)	6
	समस्त (प्रतिशत)	65 **(59.09)**	14 **(12.73)**	17 **(15.45)**	14 **(12.73)**	110 **(100.00)**	–	39 **(44.00)**	19 **(33.33)**	2 **(03.51)**	3 **(05.26)**	57 **(100.00)**	–

प्रसंगाधीन तालिका नं0 (3) के उपरोक्त निर्दिष्ट तथ्यानुसार स्पष्ट है कि सर्वाधिक वरीयता कम्प्यूटर प्रशिक्षण को प्रदान की गयी हैं। **स्व–रोजगाररतों में** बिजली मिस्त्री प्रशिक्षण को द्वितीय वरीयताएं, मोटर बाइंडिंग को तृतीय वरीयताएं प्रदान की गयी हैं; वहीं रोजगार हेतु प्रयासरतों में प्रथम वरीयता (सर्वाधिक) कम्प्यूटर प्रशिक्षण को, द्वितीय वरीयता टेलरिंग को, तृतीय वरीयता ब्युटीशियन/पार्लर कोर्स को दी गयी हैं। जो यह स्पष्ट करता है कि अधिकाँशतः युवा वर्ग ने ऐसे कौशल प्रशिक्षण कोर्सों को अधिक (उच्च) वरीयताएं प्रदान की हैं जिनसे वे अधिक अर्थोपार्जन कर सकें। यथाः ग्रामीण कृषक परिवारों के युवाओं ने 'टक्टर मैकेनिक' के प्रशिक्षण कोर्स अधिक किए हैं एवं नगरीय पृष्ठभूमि के युवाओं ने 'कम्प्यूटर' प्रशिक्षण कोर्स; बिजली मिस्त्री और टेलरिंग प्रशिक्षण। युवतियों की रूचि कम्प्यूटर के अतिरिक्त टेलरिंग, ब्यूटी–पार्लर, गृह साज सज्जा व पेण्टिंग में देखी गयी है। निम्न तालिका नं0 (4) 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' में कौशल प्रशिक्षणों से पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों के प्रसंग में सभी 200 न्यादर्शों के दृष्टिकोण दर्शाती है :

तालिका नं0 (4) : योजना से पड़ रहे प्रभावों सम्बन्धी विभिन्न शोध प्रश्नों के प्रति निदर्शितों के अभिमत/दृष्टिकोण

क्र0	प्र0 मंत्री कौ0वि0यो0 तथा कौशल प्रशिक्षणों के विभिन्न प्रभाव (योजना–मूल्याँकन)	न्यादर्शों के अभिमत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत) हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	समस्त (प्रतिशत)
1	स्वयं के रोजगार सृजन से ग्राम–नगर पलायन में कमी आयी है।	124 (62.00)	38 (19.00)	24 (12.00)	14 (07.00)	200 (100.00)
2	अपनी रूचि के लिए प्रशिक्षणों से अर्जित 'कौशल/ हुनर' से बेरोजगारी–उन्मूलन में सहायता मिली है।	140 (70.00)	20 (10.00)	40 (20.00)	–– (00.00)	200 (100.00)
3	युवाओं में कौशल प्रशिक्षणो के प्रति	162	––	26	12	200

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

	जागरूकता बढ़ी है जिसमें पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा प्रायोजित 'कौशल मेले' सार्थक भूमिका–निर्वाह कर रहे हैं।	(81.00)	(00.00)	(13.00)	(06.00)	(100.00)
4	प्र0 मंत्री कौशल विकास योजना से युवा सशक्तिकरण विशेषतः महिला सशक्तिकरण को बल मिला है।	158 (79.00)	–– (00.00)	42 (21.00)	–– (00.00)	200 (100.00)
5	''प्र0मं0 कौ0वि0यो0'' से ग्रामीण नवाचार को प्रोत्साहन मिला है।	136 (68.00)	38 (19.00)	–– (00.00)	26 (13.00)	200 (100.00)
6	'कौशल प्रशिक्षण' नौकरी के अलावा स्वरोजगारों का उम्दा (बेहतर) विकल्प है।	180 (90.00)	–– (00.00)	20 (10.00)	–– (00.00)	200 (100.00)
7	'कौशल तथा ज्ञान' आर्थिक व सामाजिक विकास के दो प्रमुख प्रेरक बल हैं।	200 (100.00)	–– (00.00)	–– (00.00)	–– (00.00)	200 (100.00)
8	युवा वर्ग की सोच में बदलाव आया है, अब वे सामान्य नौकरी करने की अपेक्षा अपना खुद का व्यवसाय करने पर जोर देने लगे हैं।	190 (95.00)	–– (00.00)	–– (00.00)	10 (05.00)	200 (100.00)
9	'प्र0मं0 कौ0वि0यो0' भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मानवीय संसाधनों तथा लघु उद्योग धन्धों के विकास में श्रेष्ठ भूमिका– निर्वाह कर रही है।	141 (70.50)	–– (00.00)	59 (29.50)	–– (00.00)	200 (100.00)
10	संगठित तथा गैर–संगठित क्षेत्रों में श्रम–बाजार के लिए कौशल प्रशिक्षितों की जरूरतों को पूरा करने में प्र0मं0 कौ0वि0यो0 अहम भूमिका निभा रही है।	156 (78.00)	30 (15.00)	–– (00.00)	14 (07.00)	200 (100.00)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका नं0 (4) के तथ्यों के विश्लेषण के प्रकाश में स्पष्ट है कि :

(1) तालिका के स्तम्भ ''हाँ'' की आवृत्तियाँ तथा तत्सम्बन्धित प्रतिशत ; यह स्पष्ट करते हैं कि प्र0मं0 कौ0वि0यो0 (PMKVY) से कम शिक्षित युवा वर्ग पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक–आथिक प्रभाव सकारात्मक है जो तालिकान्तर्गत स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट हैं।

(2) क्रमाँक (8) यह स्पष्ट करता है कि प्र0मं0 कौ0वि0 योजना के प्रभावों की वजह से युवा वर्ग के सोच बदले हैं; वे अब सामान्य नौकरी की अपेक्षा योजनान्तर्गत अपनी रूचि का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर 'खुद' का व्यवसाय करने पर जोर (बल) देने लगे हैं।

पुनः कौशल प्रशिक्षण प्राप्त सभी 200 न्यादर्शों (106 बालक/94 बालिकाओं) से पृथक–पृथक साक्षात्कारों के समय पूरक प्रश्न किया गया कि ''क्या आप अनुभूति करते/करती हैं कि शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन में 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' प्रभावी भूमिका–निभा रही है?''–न्यादर्शों से प्राप्त प्रत्युत्तरों पर निम्न तालिका नं0 (5) संक्षिप्त प्रकाश डालती है :

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं0 (5) : ''क्या शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन में 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' प्रभावी भूमिका निभा रही है?''–न्यादर्शों के प्रत्युत्तर

क्र0	''क्या शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन में 'प्र0मं0 कौ0वि0यो0' प्रभावी भूमिका निभा रही है?''–प्रत्युत्तर	कौशल प्रशिक्षित न्यादर्श		समस्त
		बालक	बालिकाएं	
1	''हाँ''	85_{A}	50_{B}	135
2	''नहीं''	21_{C}	44_{D}	65
समस्त		106	94	200

सूत्र : 'असंगत गुणाँक' (Q)

$$= \frac{AD - BC}{AD + BC} = \frac{85x44 - 50x21}{85x44 + 50x21}$$

$$= \frac{3740 - 1050}{3740 + 1050} = \frac{2690}{4790}$$

= (+) 0.5616 (उच्च कोटि)

चूँकि साँख्यकीय परीक्षण 'असंगत गुणाँक/आकस्मिकता गुणाँक' (Q) का गणनात्मक मान (+) 0.5616 (उच्च कोटि) का प्राप्त हुआ है जो उसके प्रामाणिक मान (±)1 के मध्य है जो यह स्पष्ट करता है कि ''शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना'' के मध्य संगतता है; अर्थात् शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की भूमिका सकारात्मक है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

शोध समस्या के सन्दर्भ में निर्मित परिकल्पना सत्य एवं प्रासंगिक (सार्थक) सिद्ध हुई है कि ''शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन में प्र0मं0 कौ0वि0 योजना एक महत्वाकाँक्षी तथा परिणाम आघृत सार्थक पहल'' है जिसने : (1) ग्राम–नगर पलायन में कमी की है, (2) प्रशिक्षण से अर्जित हुनर की वजह से बेरोजगारी–उन्मूलन में सहायता प्रदान की है, (3) युवा वर्ग में कौशल प्रशिक्षणों के प्रति जागरूकता जनित की है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तथा स्थानीय निकायो द्वारा प्रायोजित मेलों, ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया है, (4) युवा सशक्तिकरण, विशेषकर महिला सशक्तिकरण को बल मिला है, (5) ग्रामीण नवाचारों (Rural Innovations) को बल मिला है, (6) 'कौशल प्रशिक्षण' नौकरी के अलावा स्व–रोजगारों के उम्दा/बेहतर विकल्प हैं, (7) 'कौशल तथा ज्ञान' आर्थिक व सामाजिक विकास के दो प्रमुख प्रेरक (बल) हैं, (8) युवा वर्ग की पुरातन सोच में बदलाव आया है, साम्प्रत; अब वे साधारण नौकरी करने की अपेक्षा अपना स्वयं का व्यवसाय (रोजगार) सृजित करने पर बल दे रहे हैं, (9) भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में मानवीय संसाधनों एवं लघु उद्योग धन्धों के विकास में श्रेष्ठ भूमिका निर्वाह की

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

है, एवं कर रही है, तथा (10) संगठित तथा गैर संगठित क्षेत्रों में श्रम बाजार के लिए कौशल प्रशिक्षिता की जरूरतों को पूरा करने में 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' अहम् भूमिका निर्वाह कर रही हैं। और अधिक सार्थक परिणाम–उपलब्धि के लिए शोधार्थी की मान्यता है कि :

(1) योजनान्तर्गत 'कौशल' औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सरकारी कौशल केन्द्रों तथा निजी 'पार्टनर ट्रेनिंग सेन्टर्स' के औचक निरीक्षणों पर और अधिक बल दिया जाय ताकि अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों तथा भृष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

(2) युवकों के स्किल प्रशिक्षण हेतु उनके घरों के निकट पंचायत स्तरों पर 'मोबलाइजेशन कैम्प' आयोजित किए जांय तथा प्रशिक्षणोपरान्त युवक–युवतियों के 'प्लेसमेन्ट' कराने के लिए शासन स्तर पर 'रोजगार मेलों' के भी आयोजन कराए जांय ताकि प्र0मं0 कौ0वि0 योजना का परिणाम आधारित सफलता मिलती रहे।

(3) शहरी के साथ ही ग्रामीण युवक–युवतियों को भी 'कौशल प्रशिक्षण' देकर रोजगार सृजन के समान अवसर सुलभ कराने के यथा सम्भव प्रयास किए जांय।

(4) 'कौशल विकास मिशन' की स्थानीय स्तरों पर गठित इकाईयों को इस बात पर अधिक 'फोकस' करना चाहिए कि जो युवक/युवतियाँ पढ़े लिखे होने के बावजूद भी 'तकनीकी ज्ञान' न होने की वजह से बेरोजगार हैं; 'योजना का लाभ' आवश्यक रूप से लें, ऐसा न हो कि जन जागरूकता के अभाव की वजह से वंचित न रह जांय।

(5) 'कौशल विकास मिशन' को गत्वर बनाने हेतु 'टास्क फोर्स' गठित किए जांय। जो समय–समय पर जनपदीय तथा प्रादेशिक स्तरीय गठित 'मिशन प्रबन्धन' को आख्याएं प्रस्तुत कर योजना क्रियान्वयन के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति से अवगत कराते रहें।

(6) कौशल प्राप्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को 'एकाउन्टिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाय। मिशन के प्रबन्धक के औचक निरीक्षणों में देखने में आया है कि एकाउन्टिंग प्रशिक्षण में 50% भी नहीं मिले प्रशिक्षणार्थी [दृष्टव्य ; अमर उजाला (समाचार–पत्र) 14 फरवरी, 2018, पृष्ठ 9]; अन्यथा की स्थिति में प्रधान मंत्री का महत्वाकांक्षी 'कौशल विकास मिशन' अपनी लक्ष्य–प्राप्ति में सफल न हो सकेगा।

सन्दर्भ सूची (References) :

शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार–सृजन ; मैकेन्जी रिपोर्ट, 2017

महापात्र इन्द्रभूषण ; भारत के शिक्षित युवा चौराहे पर, 'राष्ट्रीय सहारा' 30 जुलाई 1989, पृष्ट 13

रूद्दत हुसैन ; नौकरी नहीं, काम ढूँढ़ना होगा ; ''हस्तक्षेप डैस्क'', जे0एन0यू0 दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2000, पृष्ठ 6

मालपाणी सुरेखा ; शिक्षित बेरोजगारी : कारण व समाधान, प्रकाशित शोध–पत्र, 'योजना' पत्रिका, सरकारी प्रकाशन, दिल्ली, 1992, पृष्ठ 27–31

सक्सेना आर0के0 ; शिक्षितों की बेरोजगारी ; एक समस्या, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 1996, पृष्ठ 82

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

लवानिया एम0एम0 ; समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, कॉलेज बुक डिपो एण्ड पब्लिशर्स (राज0), जयपुर, 1997, पृष्ठ 206

'हस्तक्षेप डैस्क' जे0एन0यू0, दिल्ली, 30 सितम्बर, 2000, पृष्ठाँकन 6

त्रिपाठी ए0के0 ; युवा वर्ग में बेरोजगारी की समस्या, 'आर्थिक जगत' पत्रिका, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ 12

बाबा जी0डी0; ऐम्प्लाइमेन्ट, अन–ऐम्प्लाइमेन्ट एण्ड फुल–ऐम्प्लाइमेन्ट, पुणे प्रकाशन, पुणे (प्रा0लिमि0) विद्या भारती, मेडिकल यूनिवर्सिटी रोड, पूना, 2005, पृष्ठ 110–117

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies